भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3491
दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 / 26 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में पुलिस स्टेशनों के लिए सहायता

3491. श्री सतीश कुमार गौतमः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में जिला पुलिस की सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा कोई सहायता प्रदान की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त जिलों में थानों के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कोई सहायता प्रदान की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) की समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2015 में 'राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना' को अनुमोदित किया था। इस नीति में एक बहुआयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है, जिसमें सुरक्षा संबंधी उपाय, विकासात्मक पहलें, स्थानीय समुदायों के अधिकारों एवं हकदारियों को सुनिश्चित करना, आदि शामिल हैं।

- भारत सरकार, सुरक्षा के मामले में, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की बटालियनों, प्रशिक्षण, राज्य पुलिस बलों के सशक्तिकरण हेतु निधियों, उपकरणों एवं हथियारों, आसूचना के आदान-प्रदान, फोर्टीफाइड पुलिस स्टेशनों के निर्माण आदि का प्रावधान करके वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की सहायता करती है।
- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष अवसंरचना स्कीम (एसआईएस) के तहत, भारत सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाती है:

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3491, दिनांक 17.12.2024

i. विशेष बलों का सुदृढ़ीकरण

ii. विशेष आसूचना शाखाओं का सुदृढ़ीकरण

iii. जिला पुलिस का सुदृढ़ीकरण

iv. सुरक्षित पुलिस स्टेशनों (एफपीएस) का निर्माण

जिला पुलिस और सुरक्षित पुलिस स्टेशन के लिए राज्यों को दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:

- पिछले 05 वर्षों के दौरान जिला पुलिस के लिए 363.26 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।
- इस स्कीम के तहत वर्ष 2017-18 से अब तक 759.51 करोड़ रुपये की लागत से 302 सुरक्षित पुलिस स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं।
- विशेष अवसंरचना योजना को 60 (केंद्र): 40 (राज्य) के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है।

*****